

ग्रसाबारस

EXTRAORDINARY

भाग I---सम्ब I

PART I-Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित)

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 74]

मई बिस्ली, शनिबार, सप्रैल 25, 1970/वैशाल 5, 1892

No. 741

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 25, 1970/VAISAKHA 5, 1892

इस भाग में भिन्न गुट्ट संख्या थी जाती है जिससे कि यह बालग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be flict as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

RESOLUTION

New Delhi, the 23rd April 1970

No. F.7(25)-E.III(A)/69.—The Government of India have decided to set up a Pay Commission composed of the following:—

Chairman

(1) Shri Raghubar Dayal, ex-Judge of the Supreme Court.

Members

- (2) Dr. Nihar Ranjan Ray.
- (3) Prof. A. K. Das Gupta.
- (4) Dr. V. R. Pillal.

Member-Secretary

- (5) Shri H. N. Ray, ICS.
- 2. The Commission will be required to enquire into and make recommendations on:—
 - (i) the principles which should govern the structure of emoluments and conditions of service of Central Government employees;

- (ii) what changes in the structure of emoluments and conditions of service of different classes of Central Government employees are desirable and feasible:
- (iii) death-cum-retirement benefits of Central Government employees;
- (iv) the structure of emoluments and conditions of service, including deathcum-retirement benefits, of personnel belonging to the All India Services:
- (v) the structure of emoluments including benefits in cash and kind and death-cum-retirement benefits of personnel belonging to the Armed Forces, having regard to their terms and conditions of service;
- (vi) the structure of emoluments and conditions of service, including deathcum-retirement benefits, of employees of the Union Territories; and
- (vii) while enquiring into the level of minimum remuneration, the Commission may examine the Central Government employees' demand for a need-based minimum wage having regard to all relevant factors.
- 3. The Commission will make its recommendations having regard, among other relevant factors, to the economic conditions in the country, the resources of the Central Government and the demands thereon such as those on account of developmental planning, defence and national security, the repercussions on the finances of the State Governments, public sector undertakings, local bodies, etc.
- 4. In case, in view of the increase in cost of living, the need for consideration of relief of an interim character arises during the course of deliberations of the Commission, the Commission may consider the demand for relief of an interim character and send reports thereon. In the event of the Commission recommending any interim relief, the date from which this relief should take effect will be indicated by the Commission.
- 5. The Commission will devise its own procedure and may appoint such advisers as it may consider necessary for any particular purpose. It may call for such information and take such evidence as it may consider necessary. Ministries and Departments of the Government of India will furnish such information and documents and other assistance as may be required by the Commission. The Government of India trust that the State Governments, service associations and others concerned will extend to the Commission their fullest cooperation and assistance.
 - 6. The Commission will make its recommendations as soon as practicable.

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India.

Ordered also that a copy of the Resolution be communicated to the Ministries/Departments of the Government of India, State Governments/Administrations of Union Territories and all others concerned.

P. GOVINDAN NAIR, Secy.

वित्त मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 मप्रैल 1970

सं॰ एफ॰ 7(25)-ई 111(ए)/69—भारत सरकार ने एक वेतन धायोन नियुक्त करने का निर्णय किया है जिसका गठन निम्निखित प्रकार से किया जायगा :---

ग्रघ्यक्ष

(1) श्री रच्यर दयाल, सर्वोच्य न्यायालय के मृतपूर्व न्यायाधीश।

सदस्य

- (2) डा॰ निहार रंजन राय।
- (3) प्रो० ए० के० दास गुप्त।
- (4) डा० वी० भार० पिल्लै।

सदस्य सचिव

- (5) श्री एच० एन० राय, न्नाई० सी० एस०।
- भ्रायोग को निम्नलिखित बातों की जांच करनी होगी भीर उन पर भ्रपनी सिफारिमें देनी होंगी:----
 - (i) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन के ढांचे और सेवा की शर्तों के नियासक सिद्धान्त।
 - (ii) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की भित-भिन श्रेणियों के वेतन के ढांचे भीर सेवा की शर्तों में कौन से परिवर्तन बांछनीय तथा व्यवहार्य हैं;
 - (iii) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति लाभ ;
 - (iv) श्रिखल भारतीय सेवाभ्रों के कर्म चारियों के वेतन-क्रम का ढांचा, सेवा की शर्तें तथा मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति लाभ ;
 - (V) सम्रास्त्र सेनाभों के कर्मैचारियों की सेवा की मतौं को ध्यान में रखते हुए उनके वेतन के ढांचे, नकद तथा माल के रूप में मिलने वाले लाभ ; भौर मृत्यु तथा सेवा-निवृत्ति लाभ ;
 - (Vi) संघ राज्य क्षेत्र के कर्मचारियों के बेतन के ढांचे तथा सेवा की शर्ते एवं मृत्यु तथा सेवा-निवक्ति लाभ ; भीर
 - (vii) निम्नतम वेतन के स्तर की जांच करते समय आयोग, केन्द्रीय सरकार के कर्मे-चारियों की इस मांग की भी जांच कर सकता है कि न्यूनतम वेतन आवश्यकता पर भाधारित होना चाहिए।
- 3. भ्रायोग, भ्रपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने में, भ्रन्य संबंधित कारणों के साथ साथ, देश की भ्राधिक स्थित, केद्रीय सरकार के साधनों को तथा उन साधनों पर विकासोमुख भ्रायोजना रक्षा-व्यवस्था तथा राष्ट्रीय सुरक्षा-व्यवस्था जैस प्रयोजनीं के लिए धन की भ्रावश्यकता को एवं राज्य सरकारों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों, भ्रावि के विस्तीय साधनों पर पढ़ने वाले प्रभावों को भी ध्वान में रखेगा।
- 4. घगर, जीवन निर्वाह मूल्य में वृद्धि को वेखते हुए, घायोग द्वारा किये जाने वाले विचार-विमर्श के दौरान झंतरिम किस्म को राहत पच विचार करने की धावश्यकता उपस्थित हो तो घायोग झंतरिम किस्म की राहत की मांग पर विचार कर सकता है भीर उस पर प्रपनी रिपोर्ट वे सकता है। घगर घायोग किसी प्रकार की झंतरिम राहत दिये जाने की सिफारिश करें तो घायोग इस बाबत भी सुझाब देगा कि इस प्रकार की राहत किस तारीख से दी जाय।

- 5. घायोग घपने कार्य की विधि स्वयं ही निर्धारित करेगा घीर किसी विशेष उद्देश्य के लिए कोई सलाहकार नियुक्त करने की जरूरत महसस करेगा तो ऐसे सलाहकार नियुक्त करेगा। वह जैसी जरूरी समझेगा वैसी जानकारी मंगवा सकेगा घीर वैसे साध्य ले सकेगा। भायोग ारा जो जानकारी तथा वस्तावेज घीर घग्य सहायता मांगी जायगी, वह भारत सरकार के मंद्रालयों तथा विभागों द्वारा प्रस्तुत की जायेगी। भारत सरकार विश्वास करती है, घायोग को राज्य सरकारों, सेवा संस्थाओं घीर ग्रन्य संबंधित संगठनों घादि द्वारा पूरा सहयोग तथा सहायता वी आयगी।
 - 6. भायोग अपनी सिफारिशें, यथा-शक्य शीघ्र प्रस्तुत करेगा। भादेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत में प्रकाशित किया जाय।

यह भी भादेश दिया जाता ह कि संकल्प की एक एक प्रतिलिपि भारत सरकार के मंत्रालयों/ विभागों, राज्य सरकारों/संभ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों तथा भ्रन्य सभी संबंधित संस्थाभों/व्यक्तियों भ्रादि को भेजी जाय⁷।

पी॰ गोबिन्धन नायर, सचिव।